



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

तं० 168]

नई विल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1982/भाद्र 27, 1904

No. 168] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1982/BHADRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रहा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वार्षिक भंडालय

आयात व्यापार नियंत्रण

वार्षिक सूचना सं० 45-प्राई० ट्रॉ० सौ० (प० एन) / 82

नई विल्ली, 18 अक्टूबर, 1982

विषय :—येन 1 8 विलियन की ओर ही सी एक ऋण समझौता में
आई ट्रॉ० पी० 18 के अधीन (बम्बई उप-नगरीय रेलवे आषु-
निकीकरण परियोजना) माल और सेवाओं के आयात के लिए
मालामाल शर्तें।

विसिल स० प्राई० पी० सौ० 23(33)/82—बम्बई उप-नगरीय रेलवे
आषुनिकीकरण परियोजना का सारूप करने के लिए येन 1 8 विलियन के
ओर ही सी एक ऋण समझौता म० आई ट्रॉ० पी० 18 के अधीन माल और
सेवाओं के सम्बन्ध में आयात आदेसेस जारी करने के लिए जैसी शर्तें
इस मार्विजनिक सूचना के परिणिष्ठ में दी गई हैं, वे सूचना के
लिए प्रक्रियालय की जाती हैं।

भणि नागर्यणन्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं नियंत्रण

वार्षिक भंडालय की सार्वजनिक सूचना सं० 45-प्राई० ट्रॉ० सी (प० एन)/
82 विल्ली 18 सितम्बर 1982 का परिणिष्ठ।

जापान की विदेशी आर्थिक सहकारी निधि (आई ई सी एफ) द्वारा
प्रदान किए गए 1 8 विलियन येन ऋण के अधीन बम्बई सूबवंत रेलवे
आषुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए माल के आयातों और
सेवाओं के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड 1- सामान्य शर्तें

1(1) बम्बई सूबवंत रेलवे आषुनिकीकरण परियोजना की आवश्य-
कनाओं के वित्त-वान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि
(ओर ही सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया 1.8 विलियन येन का ऋण
विकासशील देशों के लिए बुला है। तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन
आषियान की जाने वाली अनुदान और सेवाएं जापान और अनुदान 1 की
सूची में उद्दृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस ऋण
के अन्तर्गत पाल स्थान देश होंगे।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उक्ती यदों और उसी मूल्य के लिए
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महा नियंत्रण, तकनीकी
विकास/पूर्जीगत माल वर्गित द्वारा विशेष रूप में किसी निकासी कर सी
गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सी) का
मूल्य 2,000 मिलियन (पाँचन-बीमा-भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस को रूपए में मूल्य, राजस्व विभाग (मीमा शाल्क) द्वारा प्रधिकारित वित्तिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित और मुश्तक नियन्त्रक, आयात-नियन्त्रित द्वारा जारी की गई मार्ग-जनिक सूचना सं. 78/आईटी सी (पी.एन.) / 74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के प्रनुसार आयात लाइसेंस में सकेतित दर पर नियन्त्रित किया जाएगा, जिसमें यह भी उल्लेख है कि मीमा शाल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (मी) में विनिर्दिष्ट मुद्रा वित्तिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नामे डालेंगे। लाइसेंस पर एक पर्याप्तक “जारी येन” शब्द सं. 38/आईटी डी० पी०-१८ होगा। प्रथम और द्वितीय प्रस्तुति के लिए लाइसेंस में “एम/जे० एन०” कोड होगा। मार्गीय रेलवे को आयात लाइसेंस भेजते समय मूल्य नियन्त्रक, आयात-नियन्त्रित के पत्र में भी इसे दृढ़राया जाएगा। जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय प्राधिक कार्य विभाग (आयात अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) नागर-बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल भारतीय रेलवे के नाम से लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) भारतीय रेलवे की सुविधा पर निर्भर करने हुए एक से प्रधिक आयात लाइसेंस इस क्रॉडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन कुल मूल्य 2,000 मिलियन (नागर-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊरंग पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि भारतीय रेलवे द्वारा व्यावेदन करने पर 31.12.86 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो, अर्थिक कार्य विभाग (आयात अनुभाग) को मेंजी जानी चाहिए।

1(6) ओडिट के अधीन विवरान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस से संभवन माल और सेक्षनों की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत मत्यापित् हों, तक प्रतिबन्धित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेण्य की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय प्रभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय प्रभिकर्ता को भारतीय रूपए में किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इस लिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) प्रके प्रादेश अनुबंध -1 में उल्लिखित वेशों में स्थित विदेशी संभरकों को नागर-बीमा-भाड़ा के आधार पर यिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर अर्थिक कार्य विभाग (आयात अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का मुश्तकान भारतीय रूपए में भारत में किया जाएगा। “प्रके प्रादेशों” का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा दिए गए उन क्रम अदेशों से है जो या तो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रम संविदा हों। विदेशी संभरकों के भारतीय प्रभिकर्ताओं के प्रादेश और या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुस्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस रूपांक का तत्काल प्रयोगानन्दन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेकों के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, अर्थिक कार्य विभाग, (आयात अनुभाग) को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) से यथा उल्लिखित प्रके प्रादेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्षयों नहीं दिए जा सकते, इन कारणों का उल्लेख करने हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आदेशों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी

होने की तिथि से 8 महीनों से प्रधिक के लिए मार्गी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, अर्थिक कार्य विभाग (आयात अनुभाग), नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली का भेजे जाना चाहिए जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मासले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना नियंत्रण लाइसेंस प्राधिकारियों का भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैक गारंटी साथ-पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रूपया जमा करने की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की ममालित से चार महीने के भीतर मभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोत्र लदात पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेकों से नकद आधार पर अर्थात् पोत्र लदात दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किसी की अद्य रुचि सुविधा उपलब्ध करने की प्रान्तिमत नहीं दी जाएगी। माल के वित्तरण की अवधि के लिए ठेकों में निम्नलिखित प्रनुसार व्यवस्था होनी चाहिए।

“साथ-पत्र की प्राप्ति के बाद महीने परन्तु अधिक से अधिक के प्रति नक पूर्ण किया जाना है।

पोतलदात के लिए प्राविर्ती तिथि निर्दिष्ट करने से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31.12.1986 के बाद की न हो।

जंड-2 संभरण ठेकों का सम्पूर्ण करने समय ध्यान में रखी जाने वाली विवेश बातें

2(1) ठेकों का जहाज पर्यंत नि शुल्क मूल्य येन में (येन को भिन्न के बिना) अधिक्यकृत होना चाहिए और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूपए में बूकाना चाहिए। भारतीय रूपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेकों का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अधिक्यकृत नहीं होना चाहिए। क्यद आदेश और संभरक द्वारा पुस्टिकरण आवेदन केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओ०. ई०. सी०. ए०. येन कैडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिग्राह्य करने के लिए विस्तृत निर्देश प्रनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, साधारणतया माल और सेवाओं की अधिग्राहित औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए—

(क) बोली लगाने के लिए निमंत्रण भारत में मामाल्य रूप से परिचालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित करने पड़ेगे।

(ख) बोली के बाड़ या बोली लगाने की गारंटी की मामाल्य आवश्यकता है, परन्तु उनकी इतना ऊचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हलोमाल्हित ही जाए।

(ग) बोली खुल जाने के बाद अनफल बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली बांध या गारंटिया दिया कर देनी चाहिए।

2(13) जिन समालों में शैयपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निकिदा उचित न हों वहां निधि निम्नलिखित वैकल्पिक किया विधि अपनाएँ—

(क) जहां आयातक के पास विस्तमनीय कारण हों या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखना हो।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहां अधिग्राहित में शामिल अन्तराष्ट्रीय इतनी कम हो कि विदेशी कम स्पष्ट रूप से विलब्स्थी न ले या शैयपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के कायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्व पूर्ण हों।

(प) अपर (क), (ख) और (ग) के प्रतिक्रियत जहा निधि और-चारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया का अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपात प्रधिप्राप्ति के मामले में ।

ऊपर सकेतिन मामलों में, निम्नलिखित प्रधिप्राप्ति प्रक्रिया इस रूप से अपनाई जाएँ जिसमें जहा तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके ।

- (1) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना ।
- (2) अनोपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियोगिक प्रधिप्राप्ति ।
- (3) एक सभरक से सीधा कद विशेष कारण, औपचारिक सामाजीकों के ।

भारतीय रेलवे का अहुण कंगार नदी किए जाने के तहकाल बाद ही निधि अं० १०० रु० सी० एक० का इसकी पुनरीक्षा के लिए बोर्डीकोंकारों के लिए सभी नोटिसों और अनुदेशों, बोली प्रथम, प्रस्तावित सर्विदा, विशिष्टिकरण और द्वाइग, बोली विश्लेषण की रिपोर्ट, एकार्ड के लिए प्रस्ताव, और बोली से सबद्वय सभी मगान वस्तावेज भेजेगा । औ० १०० सी० एक० को इस्तावेज भेजने के लिए, ये इस्तावेज दो प्रतियों में अवर संचित (टी.ए) प्राथिक कार्य विभाग को भेजे जाएँ ।

2(4) विवेशी सभरक का भुगतान, उनके नामे भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1979-80 के लिए औ० १०० सी० एक० येन ब्रेक्ट (पर्योजना महायाता) स० अ० १०० पी० १८ के अवधीन खोने गए अवरिक्ततायी भाष्य पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसका द्वारा भीने अंड-६ में दिया गया है ।

2(5) आयात लाइसेन्स के प्रति केवल एक ही सर्विदा की जानी चाहिए । लेकिन, कुछ विशेष सामग्री में, एक से प्रधिक सर्विदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेन्स आरी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित सवालाय, प्राथिक कार्य विभाग (जापान अनु-भाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

2 (6) सभरक की पाकता

सभरक पात्र स्वोत देशों का नागरिक या पात्र स्वोत देशों में समाविष्ट और पर्याप्त व्यक्ति है और पात्र खोत देशों के नागरिकों द्वारा नियक्त है ।

2 (7) सर्विदा में घोषणा

प्रत्येक सर्विदा में सभरको द्वारा पाकता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा ।

“मैं, प्रधोहस्ताक्षरी एवं द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि सभरित किया जाने वाला माल में (पात्र स्वोत देश) उत्पादित है ।

मैं, प्रधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुमार आपात स्वोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूचक के अनुमार 30% से कम है ।

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क

× 100”

सभरक का जहाज पर नि शुल्क मूल्य

“मैं, प्रधोहस्ताक्षरी, एवं द्वारा सन्धारित करता हूँ कि ।

(पात्र स्वोत देश का नाम) में (कार्मी का नाम) समाविष्ट और पर्याप्त हो चुकी है और पात्र स्वोत देशों के नागरिकों द्वारा नियक्त है ।

2 (8) प्रयत्र स्वीत देशों से अनुमेय प्राप्ति

जिन दस्तुओं में असाव द्वारा देशों में बनी हुई सामग्री निहित है, उनका वित दान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूचक के अनुमार मर-वार प्राप्तार पर आयातित भाग 30 प्रतिशत में कम हो ।

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क

× 100

सभरक का जहाज पर नि शुल्क मूल्य

खण्ड - 3 सभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्त

3(1) सभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष स्वप से समाविष्ट होने चाहिए ।

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी प्रार्थिक सहयोग निधि (ओ० १०० सी० एक०) के बीच बालै अवर्द्धन रेलवे अध्यानिकारण परियोजना के लिए येन क्रेक्ट अ० १०० पी० १८ (पर्योजना महायाता) से सबधित 14 मई 1982 को हुए अस्त्रग सभरों के अनुमार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विवेशी आयिक महायोग निधि के अनुमोदन के प्रवीन होगा ।

(ख) सभरको को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विवेशी आयिक महायोग निधि (ओ० १०० सी० एक०) के बीच येन क्रेक्ट म० अ० १०० डी० १८ से सबधित 14 मई 1982 को हुए अहुण सभरों के अन्वर्तन बैंक आफ हिडिया, टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अवरिक्ततायी मालवर्तन के माध्यम से किए जाएं ।

(ग) विवेशी सभरक ऐसी सूचना और वस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा तो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और ओ० १०० सी० एक० द्वारा येन अहुण के अवर्द्धन अर्वाचित हो ।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रत्यक्ष में प्रमाण पत्र (सीत प्रतियों में) ।

3(2) यदि किसी मामले में सभरक आपान में स्थित हो तो सभरण मविदा के सबध में एक धारा होनी चाहिए कि जारीनी सभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवर्तन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, गार्मिल भाल की सुपुर्देशों के कार्यक्रम से अवगत कराएगा । और पोन-लदान कन में कन 4 मानाह पूर्वी भारतीय दूतावास को सूचना देगा, जिसके लिए उल्लिखित व्यवस्था हो सके । विवेशी मालवों में, जहा भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस प्रधिधि को कभ किया जा सकता है । जापानी सभरक को प्रत्येक पोन-लदान के पश्चात आवश्यक व्याप्रे देने हुए तार में सूचना भेजने के लिए भावन होता चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजनी जानी चाहिए ।

खण्ड - 4 विवेशी आयिक सहकारिता निधि (ओ० १०० सी० एक०) द्वारा देके का अनुमोदन

4(1) लाइसेन्सधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय रेलवे और विवेशी सभरको दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियों जो विवेशी सभरक द्वारा निम्नित में पुष्ट आवेदन का था या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों समान वैध आयात लाइसेन्स की दो फोटो प्रतियों सहित जापान अनुभाग, आयिक कार्य विभाग वित मवालय, नार्थ लाल, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

4(2) उपर्युक्त किया विधि मामी ठेकों के लिए और और ठेकों की विधि वस्तु के लिए अतिवार्य आयोगों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी ।

खण्ड-5 विदेशी सभरकों को अगतान साक्ष-पत्र किए-विधि

५(१) विदेशी आर्थिक भूकालिता निवारण (ओ०६०सी०एफ०) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर विन मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा ओ०६०सी०एफ० और महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियन्त्रक को उपर्योग सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद भारतीय रेसवे को महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियन्त्रक (जिसे इसके बाद सी०ए० ए० ए० ए० कहा जाता है) आर्थिक कार्य विभाग, विन मन्त्रालय पूरे सी० ए० बैंक विहिंडा, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-३ के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रार्थिकार पत्र जारी करते के लिए अनुरोध करता थाहिए। सी०ए०ए० ए० ए० अनुबन्ध-४ के रूप में संलग्नक प्रपत्र में एक प्रार्थिकार पत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबन्ध-५ (वास्तविक आयतों के लिए) या अनुबन्ध-६ (सेवाओं के लिए) के रूप में संलग्नक प्रपत्र में संबंधित विदेशी समरूप के नाम में अन्वितर्तीय माला-पत्र खोलने के लिए जारी करेगा। प्रार्थिकार पत्र की प्रतियो (श्रेष्ठी आर्थिक सहकालिता निवारण) (ओ०६०सी०एफ०), भारतीय हूतावास, टोकियो भारत में आयतक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मन्त्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

मी.०४०.०० एड.०० से प्राधिकार पत्र के आधार पर साथ पत्र छोलने के लिए उपर्युक्त क्रिया विधि संविदा संशोधन या प्रत्यक्षा आवश्यक समझे जाने वाले हैं कि सभी प्राधिकार पत्र/साथ-पत्रों के संशोधनों पर स्वतंत्र लाग छोली ।

5 (3) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी संभरक प्रबन्धन बैंकरों के माध्यम से साथ पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो का प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज मही पाप गए तो वैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद धनराशि की लागत का धनराशि की प्रतिपूति विदेशी आधिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) सार्व-पत्र को खोलने रख-रखाव और परिकालन पर किए गए सभी खर्च विदेशी संभरकों या आयातिक के लिये में जाएंगे। प्रतः भारतीय बैंक, टोकियो संभरक बैंक या आयातिक से सभी खर्च प्राप्त करेगा, दस्तावेजों को सम्पाल के रखने और मोल-नोल करने और अन्य आकस्मिक खर्चें भी संभरको/आयातकों द्वारा किए जाएंगे।

संभरको को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यंत निःशुल्क माल की लागत के भुगतान की तिथि और ००.००.००.००.०० द्वारा प्रतिवृत्ति की तिथि के बीच के समय का व्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ २५-३-८० को हुए समझौते को शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिवृत्ति भारतीय हूतावास टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय हूतावास जापान द्वारा व्याज भुगतान पर किया गया एवं भारतीय रेलवे [विवेक ब्रांड - ६ (४)] में प्राप्त किया जाएगा।

प्राप्ति-6 एवं प्राप्ति-निष्क्रेप करने के लिए उत्तरवाचिक

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिवर्त्त में संकेतित भूमार प्राथात्कृत के प्राधिकृत बैंकर को परामर्श जहाजरानी

दस्तावेज भेजेगा और बैकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाज-रानी दस्तावेज इस्ता होने से पहले भारतीय रिकॉर्ड बैक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैक, तीस हजारी, दिल्ली में सप्ताह नियंत्र कर दिया गया है। विदेशी संघरकों को किए गए ये भूगतान के सम्बन्ध मध्ये सार्वजनिक सूचना में 7-4 प्राइंटीर्मी० (पी०एन०) / 74, दिसंक 31-5-1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लिए में जास किया जाए।

आधारानक आधारित माल का विवरण संभरक को विवेशी मुदा में भुगतान के समतुल्य रूपया निदेश करने के पश्चात् केवल बैकर से प्राप्त किए गए मूल लशान दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् करेगा । विवेशी संभरक को किए गए ये भुगतान के समतुल्य रूपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विविध की दर भुगतान की तारीख को लागू विविध की वह मिश्रित दर होती जो सार्वजनिक सूचना सं 109 आई० टी०म०० (पी०न०) / 74, दिनांक ३-४-७४ प्रीर सं 8-आई०टी०सी० (पी०एन०) / 76, दिनांक १७-१-७६ में निर्धारित तरीके के अनुसार निर्णयत की गई हो जो मुक्त नियवक, आधारान-नियति की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारीय रिकॉर्ड के मुद्रा विविध नियंत्रण परियों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर योषित की गई हो । इस लेखा रूप्य में उपर्युक्त रूपया निदेश किया जाएगा वह “हे डिपो-जिटम पैंड एडवाइज़-४४३ मिसेल डिपोजिटम-डिपोजिटम फार परवेजीज पटस्ट्रा एंड्रोड धर्चेज अन्डर कोइट्स/लीन प्रीमेट” लोग फोम दि गवर्नर्मेट प्राप्त जापान १.८ विलियन येत कोइट्स सं ८-आई०टी०पी० -१८ फार ब्रम्ही सुबबर्न रेलवे आधारिकीकरण परियोजना होता छाहिए ।

6(2) कंपर उन्निलिखित धनतराणि या या भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक भारत इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साक्ष में भारतीय सूचना संघर्षा 184-प्राईंटी०सी० (पी०एन०) /68, दिनांक 30-8-1968, सं० 233-प्राईंटी०सी० (पी०एन०) /68, दिनांक 24-10-1968, सं० 132-प्राईंटी०सी० (पी०एन०) /71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-प्राईंटी०सी० (पी०एन०) /74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-प्राईंटी०सी० (पी०एन०) /76 दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके में यथा होना चाहिए ।

6(3) भारत मरकार विभ मन्त्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी माप किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह प्रतिक्रिया धनराशि सेवा खब्बों के निमित्त भेजेगा जो विभ मन्त्रालय (प्रार्थिक कार्य विभाग) द्वारा मार्गी जाए। चालान के विभिन्न कालियों को भरने में भव्य आयातको/उनको बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटी०८० (पी०८०८०) /71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेण्य और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण व्यापे" में निरपावाद स्पष्ट में निर्दिष्ट किए गए हैं। यद्याना चालान में निम्नलिखित व्यापे निरपावाद स्पष्ट से प्रस्तुत करने चाहिए —

(क) विस सन्नातय के प्राधिकार पन्न स० प्र० और विनांब

(क्र) येन मुद्रा की वह धनराशि नियमके संबंध में भवनाई गई परि-
वर्तन वी तर के साथ नियमेप्रिया जानेहै ।

(ii) विदेशी संस्कृत की अवधारणा का विवरण।

टिप्पणी .- भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रूपए का निष्पेप भारतीय बैंक, टोकियो से अदायी की सूचना और अपरिवर्तीय पोल लदान इत्यावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपक्षाद रूपा में किया जाना चाहिए और यह कि इसके लक्षण बाकी मौजूदा ५०,००० एंड ५० वित्त मंडलाय (आधिकारिक कार्यविभाग) नई विली को संचित कर दिया जाएगा ।

6(4) भारत में सबद्ध भारतीय बैंक की लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्राप्ति पर गया नियोगी की धनरक्षण का प्रश्नाकात्म करना चाहिए, और अपेक्षित “एम” प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजना चाहिए।

भारतीय बूतावास, टाकियों द्वारा भारतीय बैंक, टोकियो को ब्याज व्याचे आदि के संबंध में येत की समतुल्य रुपए से किए गए भुगतान की गणना भी उपर्युक्त छड़ 6 की कठिका 6 (1) में निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी। मुख्य लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम में जाप किया जाएगा जिसके लिए सी० ए० ए० ए० ए० उचित अनुदेश जारी करने रहेंगे।

बंड-8 विविध व्यवस्थाएं

8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पोल-सदान और उसके प्रधीन किए गए भुगतान और शेष धनरक्षण के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक सामिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक, आर्थिक कार्य विभाग, विद्युत मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, समद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) सभरकों को विरोध शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी का आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबोधों से सभरको को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने ले जाने में सभरक पर प्रभाव डालती हों।

8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और सभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उचादायित नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टाकियों द्वारा किए गए भुगतान से पहले सभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-3 में “भुगतान की शर्तें” के अन्तर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देनी चाहिए। सविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सबद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

8(4) अविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी भासलों में संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येत केडिट समझौते (परियोजना सहायता) म० आई ३१-१८ के प्रधीन सभी आपारों को विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान (ओ ई सी एफ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय भमय पर जारी किए गए नियोगी, अनुदेशों या लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपर्युक्त छड़ों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-नियाच (नियंत्रण) अधिनियम के प्रधीन उचित कारंबाई की जाएगी।

8(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबंध-1 पात्र स्वीकृत वेशों की सूची
2. अनुबंध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग-वर्णन
3. अनुबंध-3 अधिकारपत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबंध-4 प्राधिकारपत्र का प्रपत्र
5. अनुबंध-5 साख-पत्र का प्रपत्र (पास्सविक आयातों के लिए आग्र.)
6. अनुबंध-6 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए)

अनुबंध 1

पात्र स्वीकृत वेशों की सूची

- (क) विकासशील केश तथा उनके खेत्र
 - (क-1) ओ० पी० ई० पी० से विश्व विकासशील देश
 - 1 अफ्रीका उत्तरी सहारा
 - पिथ्र
 - मोरोको
 - तुनीशिया
 - 2 अफ्रीका दक्षिणी सहारा
 - अंगोला
 - दोम्बोन्या
 - वरण्डी
 - केनेन
 - केप वर्डी ड्रीप समूह
 - केन्द्रीय अफ्रीका गणराज्य
 - चाद
 - कमोरो ड्रीप समूह
 - कागो डाहिये का गणराज्य
 - भूमध्य गिनी (1)
 - इथोपिया
 - गाम्बिया
 - धाना
 - गिनी
 - ग्राइवरी कोम्प
 - केनिया
 - लेसोथो
 - लाइबिरिया
 - मालागासी गणराज्य
 - मालावी
 - माली
 - मार्गिनेनिया मारीशम
 - मुजास्तिक
 - नाइजीर
 - पुर्तगाली गिनी
 - सियुनियन
 - रोडेशिया
 - रवान्दा
 - सेन्ट हेलिना और फ्रेंच (2)
 - सालोमोन और प्रिन्सीपल
 - सेनेगाल
 - सिल्वाज
 - सियरा लिओन
 - सीमालिया
 - सुडान
 - डवाजी लैण्ड
 - टेरी आफर्स और इस्साम
 - टोगो
 - यूगांडा
 - संजामिया संयुक्त गणराज्य
 - अपर बोल्टा
 - जाइने गणराज्य
 - जाम्बिया
 - जाम्बिया उत्तरी और दक्षिणी
 - बह्राम
 - आन्त्रोम
 - आलोज

वेरमूह
कोस्टारिका
कूट्या
डोमिनिकन गणतन्त्र
एलसाचेडोर
खाटे लौप
ग्वाटे माला
हेली
होण्डूरस
जेमेका
मार्टिनिका
मैक्सिको
नीदर लैण्ड एमटिलीज
निकार गुवा
पनामा
सेन्ट पियरो और मिक्लोन
ट्रिनिडाड और टोबागो
वेस्ट इण्डीज (शाखा) एमआईई
(क) सम्बद्धित राज्य (1)
(छ) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्का लैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसीसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बेल्जियन
इजराइल
जोड़न
लेबनान
ओमन
सिरिया अरब गणतन्त्र
यूनाइटेड अरब अमीरात (3)
यमन अरब गणतन्त्र
यमन जनवादी डी० आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया

भाफगानिस्लाम
बागला देश
भूटान

बांगलादेश
(1) पहले सेनी गिनी का प्रदेश, करनेस्टो पो द्वीप सहित
बिनी
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित
कोलम्बिया
असेस्तान, क्रिस्टन डा इन एसेसियिटम, वाइटिसेल गाफ काफ सैण्ड
द्वीप समूह
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरब, बोरेरे क्यूराकमो साहा, सेन्ट युस्टामिम,
सेन्ट फ्रांसीसी गिनी
मार्टिन (दक्षिणी भाग)

वर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका
7. सुदूर पूर्वी एशिया
बरनी
हायकाग
ख्वेर गणतन्त्र
कोरिया गणतन्त्र
लाओस
मकाओरी
मलेशिया
फिलिप्पीन
मियानुर
नाइजीर
पाइनीण्ड
तियोन
वियतनाम गणतन्त्र
वियतनाम जनवादी गणतन्त्र

8. ओसियिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्वर्ट और इलाइस द्वीप
फासिमी पोलिनेशिया (5)
नीरु
स्यु कनेडोनिया
स्यू हेब्रिसिल हैमिसेस (बा० और बे०)
नियो
स्यैमिफिक द्वीप समूह (सयुक्स राज्य) (6)
पापुआ न्यु गिनी
सालोमत द्वीप समूह (बा०)
टोगा
बालिस और फ़ूतुना
पश्चिमी समाना

9. दूरोप

माइक्रोप्रेस
जिब्राइल
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप समूह एटिगुआ, डोमिनिका, गेनाइा, सेन्ट किट्स
(मेट करिस्टोफे) नेविम-एनियुला, सेन्ट लुसिया और सेन्टविंसेट
(2) मुख्य द्वीप समूह — मोन्टेसेरान, सेमान, तुर्कम और कोर्फ्कोस और
प्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह
(3) अजमान, दुबई, फुजाइरह, रास अल क्वेमाइ, शरजाह और उम
अल क्वेन
(4) अदन और विमिश मुलतनत और अमीरात सहित ।
(5) सोमाली द्वीप समूह (ताहिरी सहित) को शामिल करने हुए
आस्ट्रेलिया द्वीप समूह टुम्बामोटु काम्बीअर ग्रूप और माकोसम द्वीप समूह ।
(6) पेसिफिक द्वीप समूह को ट्रस्ट प्रवेश, कोरोनीन द्वीप समूह,
मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क-2) छो. ०० फ० ०० सौ० के सबस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
ओलिविया
लिबियान अरब गणराज्य
गेब्रान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
बेन्जुएला
हिरान
ईरान
ईराक
कुवैत
कानार
सऊदी अरब
अबूदाब्दी
इण्डोनेशिया

अनुबंध 2

ओ००५०सौ००एक द्वारा व्यवस्थित परियोजना के अधीन माल और सेवाएं प्राप्तिप्राप्ति करने के लए भुवन भाग वर्तम

1. विज्ञापन :

ओपजारिक खुली, अल्जीरिया विविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली अतिरिक्त करने के लिए अग्री देश में सामान्य प्रचार के लिए कल से कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति होनी चाहिए।

2 बोली के दस्तावेज और संविदाए

2.1 बोली बोड और गारंटियों

बोली बाह या बोली की गारंटियों साधारण अवश्यकताएं हैं लेकिन, इनको इन्होंने कठिन नहीं बनाना जिससे कि उचित बोलीकार हूतोल्लाहित हो जाए। बोली बुलने के पश्चात् जैस ही मंत्र हो तो वो अप्रत्यारोपित बोलीकारों को दिला कर देनी चाहिए।

2.2 संविदा की शर्तें :

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किसी परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में आयातक और लेकेदार या सभरक के अधिकार और दायित्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभ्रामित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें जिनमें से कुछ का उल्लेख इन विदेशन विनियोगों में किया गया है, के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और ग्राफार :

संविदाएं, निपातित काम के लिए इकाई मूल्य के या अवैदित मदों के या एक मुल्य कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सवालों के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है या और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में भी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।

आसाविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुद्यत आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, नियंत्रित की जानी चाहिए।

इंजीनियरिंग, उपस्कार और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि अग्री देश के लिए तकनीकी और सामिक सामं प्रदान करे तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र सभरक

वे नियानिक या सभरक जिनके माल एवं मेंद्रों का वितरण अग्री को रकम में से किया जाता है (जिसे इसके बाद 'पात्र माल' कहा गया है), पात्र स्वीत देशों के राष्ट्रिय द्वारे और विदेशी देशों को पूरा करेग।—

- (1) प्रभिवान किए गए देशों का पात्र वडा भाग पात्र स्वीत देशों के राष्ट्रिय द्वारा देश जाएगा।
- (2) पूर्णांकालिक विदेशों का बहुमत पात्र स्वीत देशों के राष्ट्रियों का होगा।
- (3) ऐसे न्यायिक 'व्यक्तियों' का पंजीकरण पात्र स्वीत देश में होगा।

3. संविदा की कीमत :

(क) संविदा की कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए वर्गों की संविदा की कीमत का अह भाग जो ठेकेदार अग्री के देश में खर्च करेग अग्री की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(क) मूल्य समजन द्वारा एः—

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होता चाहिए कि पक्षों कोंसर्वों में वृद्धि की अवश्यकता है अथवा बोली कोंकरों में वृद्धि मानी है।

पर्दि संविदा के प्रमुख लागत अवधारों अर्थात् अम और महत्वपूर्ण मामधी की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा को कोंकरों में समजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोला दण्डावतों में इस साक परिभ्रामित होना चाहिए।

माल की मूल्य एं के लिए संविदाओं में कोंकरों के समत्र की उच्चतम नियंत्रित सोमा की शी शामिन किया जाता चाहिए लेकिन विविध कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम नियंत्रित सोमा का प्राय शामिन नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुर्द किए जाने वाले भाग के लिए मूँद समजन की व्यवस्था प्राय नहीं होनी चाहिए।

ये मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उत्तरों के परिवर्त का आभास नहीं होती है जिनके द्वारा संविदा मूल्य समजन हित जा सके।

4. बोली :

मकल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बोली को किसी का बोली वस्तावजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 बोलों पार्टियों द्वारा विधिवत् हृष्टान्तिर संविदा या विवेशी सभरक द्वारा लिखित स्वप में पुस्तिकरण आदेश से समर्पित क्रय प्रावेश औ पार्तीय आवासक द्वारा विवेशी सभरक को दिया गया है, या इनकी पांडी प्रतियों भी काढ़ को स्वीकार्य है।

3.3 प्रत्येक संविदा में सभरक की पत्रना का निम्नलिखित विवरण जाओ जायेगा :—

'मैं (हम) एतद्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कंपनी पात्र सभरक है, क्योंकि देशों का प्रतिशत (%) (पात्र स्वीत देश) के राष्ट्रियों द्वारा गया है, और प्रतिशत () निदेशक (पात्र स्वीत देश) के राष्ट्रिय हैं, मेरी (हमारी कंपनी) (पात्र स्वीत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4.1. मानवांश

यदि उन राष्ट्रीय मानवांशों का उल्लेख किया जाता है तिनके अन्तर्मार ही उपकरण या माल है, तो विशिष्टिकरण में यह दर्शयि जाना चाहिए कि जापान मौद्रिक मानवांश या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मानवांश को पूरा करने वाली पर्यावरण जो मानवांशों की कौटि के बराबर या उससे अधिक मानवांश का सुनिश्चय करती है उन्हें भी स्वीकार कर दिया जाएगा ।

4.2 बाल नामों का प्रयोग :

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की प्रतिश्वकना है या यह निश्चय किय, गय, है कि कुछ भास्त्र आवश्यक विषयनाओं को बनाए रखने के लिए मानवीकरण की एक हिस्ती भी आवश्यकना है तो विशिष्टिकरण निष्पादन जामता पर प्राधारित होने चाहिए और उन्हें केवल खड़, भास, सूची, संख्या या विशेष विनिर्माण के उत्पादों की निर्धारित करना चाहिए । बाद वाले भास्त्र में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पर्यावरणों के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता पिलानी-जूलानी है और कम से कम उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं ।

4.3 गारंटी निष्पादन बांड और रखो गई अनुरागी :

सिविल कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जामत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा यह जामत या तो बैंड गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी घनराशी कार्य की और परिमाण के अनुमार भिन्न-भिन्न होती है, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के भावने में अट्टी की सुखाप्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए ।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में बुद्धि की जानी चाहिए । गारंटी या अपेक्षित बांड की घनराशी को बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए ।

मान की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह बांछनीय होता कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखो गई घनराशी के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए । रोक रखो गई घनराशी को कुल भुगतान की दर मानना और इसके प्रतिसम भुगतान के लिए याते बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड बुना जाता है तो वह केवल जामत व घनराशी के लिए ही होना चाहिए ।

5. चुनाई जाने वाली अति :

अट्टी को जब कार्य पूर्ण होने या सुरुर्वाटी में देर होने के कारण फालतू अच्छा, राजस्व की हानि या प्रब्लेमों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुनाई जाने वाली अति से सम्बद्ध संविदा जामिल होना चाहिए । ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले सिविल निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब समय से पूर्ण किया गया कार्य अट्टी को नामकरी हो तो ठेकेदार को बोलन देने के लिए भी अवध्या की जाए ।

6. आज्यकारी परिस्थितियाँ :

बोली दस्तावेजों में जामिल की गई संविदा की भाँती में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में धाराएँ होनी चाहिए कि संविदा के प्रलग्नत पर्टी द्वारा अपने वायिवाँ को न पूरा करना उस द्वालम में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवर करने वाली स्थितियों में फोर्स मज्जों के फलस्वरूप हुई है (संविदा की भाँती में इसकी परिभाषा दी जाती है) ।

7. भगवां का निपातन :

भगवां के निपातन से संबंधित अप्रस्थान संविदा की भाँती में जामिल की जानी चाहिए । यह बालीय है कि धरातार अवश्यिक वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए ममझों और मध्यस्थ विरोध के दिनों पर या अन्य ऐसी अप्रस्थान जो भारतीय आयतक और विरों साथ की दिनों का स्वीकार्य ही, पर अवश्यिक होने चाहिए ।

8. भाषा की व्याख्या :

बोली दस्तावेज प्रवेशी में तैयार किए जाने चाहिए । यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेवाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अप्रेशी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि उनमें भी भाषा प्रमुख है ।

9. बोली ज्ञालना, मुख्यकान और ठेका देना :

9.1 बोलियों के आवंशक प्रस्तुत करने के बोच का समय :

बोली संयार करने के लिए प्रभुमित मन्द अधिकार मंदिर को महावना और वेचीवरी पर निर्भय करेगा । मध्यारथ अवश्यिक बोली के लिए कम से कम 30 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए किस्ति प्रमुख मम्पत्र प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों की व्याप्ति में रखने हुए होना चाहिए ।

9.2 बोली ज्ञालने की क्रिया क्रियि :

बोलियों की अन्तिम पावनी के लिए और बोली लाने के लिए नियम, समय और स्थान को बोली असंकेण में धोयन किया जाना चाहिए और सभी बोलियों निर्वाचित समय पर खुने आम बोलनी चाहिए । इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना बोलने ही लौटा देना चाहिए । यदि उन्हें अनुरोध किया है या उन्हें प्रमुखति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोलीकार और किसी वैकल्पिक बोलियों को कुल धनराशि जोर से पही जानी चाहिए और उन्होंने रिकार्ड कर देना चाहिए ।

9.3 बोलियों का स्वल्पीकरण या उनमें परिवर्तन :

बोली खुने के पश्चात् किसी भी बोलने वाले को उनकी बोली में परिवर्तन करने की प्रमुखति नहीं दी जानी चाहिए । बोली के मूल सत्र में कोई परिवर्तन नहीं दिया जाये । आयतक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह मक्का है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के सारांश एवं मूल परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए ।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रियावधि :

कानून द्वारा यथा अपेक्षित की गोड़कर बोली को खुने के बाद बोली से संबंधित निरीकण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यकान और निर्गत से संबंधित सिफारियों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियावधियों से ग्रीष्मारिष्य सम्पर्क में संबंधित नहीं है नब तक नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि सकल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को धोयन नहीं कर दिया जाता है ।

9.5 बोलियों की जाँच :

बोलियों के खुने के बाद इसका मुत्तिरिचर कर देना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गतीयों तो नहीं लिया दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के प्रमुखतर हैं क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवृहत्यान्वयन है और क्या बोलियों मानान्यत, अन्यथा अपने सही गतीयों में उपलब्ध हैं यदि बोलियों मूल रूप से विशिष्टीकरण के प्रमुखतर नहीं हैं या उनमें अस्तीकृत शांति है या अन्यथा अपने रूप में बोली सम्बद्धीकरणों के अनुत्तर नहीं हैं तो उन्हें अस्तीकृत किया जाना चाहिए । इसके बाद प्रत्येक बोलों के मूल्यकान के लिए और बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विधिवृहत्यान्वयन किया जाना चाहिए ।

9. 6 बोलीकार की पूर्व प्रोग्रामाएँ :

पूर्व प्रोग्रामाओं की अनुपस्थिति में आधारित हो चाहिए कि वह इस बात का मुनिष्यव्य कर कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्राप्ति है ये से चलाने के लिए अपना है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन प्रोग्रामाओं को पूरा नहीं करता तो उन्हीं बोली का अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9. 7 बोलियों का मूल्यांकन और विवाद :

बोलियों का मूल्यांकन बोली वस्तवावेजों में निर्भावित नियमों एवं नियमों के अनुसार होना चाहिए। अधिकारीय गवर्नियों के लिए समर्जित बोली की कीमत के अनुरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुण्डला एवं अवस्था या फालू तू पुरी की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वासनीयता का विवाद ये सिया जाना चाहिए। जहाँ तक सभव हो वे बोली वस्तवावेजों में विशिष्टिकृत मानदंड के अनुसार अपेक्षित जीवन से भिन्न होने से व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में जामिन की गई समर्जित कीमत के लिए कुछ दूसरी विवाद में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मूला अवस्था मूद्राएँ जिनमें मूल चुकाने का प्रस्ताव दिया जाता है तो बोली स्वीकृत होने पर अपनी द्वारा मूलानन दिया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना अपनी द्वारा चुनी गई एक ही मूल में भूत्तरांकित होनी चाहिए और इसका उत्पेक्ष बोली वस्तवावेजों में भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विवेकम की दृष्टि सरकारी छोल द्वारा प्रकाशित विवर दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मूला के मूल्य में कोई परिवर्तन न दिया जाए तब तक बोलियों बाल्समें के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे भाग्यों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करने समय विनियम की दृष्टि उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9. 8 बोलियों को अस्वीकृत करना :

बोली वस्तवावेजों में सामान्यतः यह अवस्था की गई है कि अपनी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों का अस्वीकार नहीं करता जाहिए और नहीं बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयाप्त जनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नहीं बोलियों अवधित नहीं की जानी चाहिए। यह उन भाग्यों को छोड़कर होगा जहाँ न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जानी है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी यह अधिकारीय देने चाहिए। जहाँ—

(क) बोलिया, बोली वस्तवाव के आधार के अनुसार नहीं है, या

(ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपनी को जाहिए कि वह उस कारण यों उस कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति मिठ की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिवर्तन पर (या बोलियों के लिए मूल आमदार में मानी गई पर्यवर्तनों की धनराशि पर) या दोनों पर विवाद करें। विशेष परिवर्तनियों में लिधि पर विवाद करने के बाद अपनी मूल्यांकनक भवित्वा प्राप्त करने के लिए किसी एवं कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या वो बोलीकारों के माध्यम सौदा कर सकता है।

9. 9 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उम बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और विलोय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार वे लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक गते के रूप में विशिष्टिकरण में निर्भावित पर्यवर्तनों के लिए या अपनी बोली को परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदारी ने।

सम्बन्ध 3

बोलीकार पर जारी करने के लिए प्रावेदनावधि

संविदा दिनांक

सेवा में

महायाता लेखा नवा लेखा परीक्षा विवेदन,
वित्त वंचालय,
प्राधिक कार्य विभाग,
य० सी० श०० वैज विलिंग, प्रदन मत्रिन,
पारिवारिक स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय --येत केहिंड स० श००० श०००-१८ (परियोजना, महायाता) 1979-80 के अन्तर्गत जारीत में का प्रयोग।

महोदय,

उपर उल्लिखित येत केहिंड श० श००० श०००-१८ (परियोजना महायाता) के अधीन में के प्रावेदन के संबंध में (वैज का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (इ) में सम्बद्ध सम्बुद्धरत संभवक के नाम में साथ पहले बोलने के लिए दिया गया है, को प्राधितार पर जारी करने के लिए इस प्रपको निर्माणित उपर्युक्त उपयोग तकनीकी विवाद करने हैं—

(क) भारतीय प्रयोजन का नाम और पता।

(ख) प्रायाम लाइसेंस की मंड़ी, दिनांक और प्राप्त वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके क्षमा यह संझें करें कि अपैचारिक बूले अस्तरांस्ट्रीय लिविदा पर आधारित है। इसके मानसे में यदि कोई कारण हो तो कारण महिन या संकेतिन होना चाहिए कि वह विवाद का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के प्राप्तार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(इ) माल का उदासम देश

(ज) यदि कोई हो तो पत्र से इन द्वारा देशों से आयातित संभवतों का प्रतिवाद।

(झ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येत में)

(ञ) परि कोई हो तो भारतीय एजेंट के क्षेत्र की अस्तरांस्ट्री (येत में)।

(ञ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येत में) जिसके किए प्राधिकार के पत्र मार्गा गया है।

(ञ) सम्बुद्धरत के संभवों के नाम की गई संविदा की मंड़ा एवं दिनांक।

(ट) सम्प्रैरात्र के संभवक के नाम और पता।—

(१) राष्ट्रिकान।

(२) पत्र औल देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए वेयरो के प्रतिवाद।

(३) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकाना और/या संपरक का निवास स्थान।

(४) उन निवेशों का प्रतिग्राम जो पत्र औल देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ञ) ये न्यूनतम शर्तें और संभावित लियाया जिसको संविदा के सम्बन्धीन भूगतान देय होंगे।

(ञ) सूपुर्वी को पूर्ण करने की प्रायामित लियि।

यदि कोई हो तो, बैक के बीच, व्याज और बैक आफ इहिया। टॉकियो शास्त्र के अन्य खंड (जिसमें विदेशी सभरको के बैकरा के बीच भी शामिल हैं) प्रमुख लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को समनुच्छ रूपां भवा करने पर ही तय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, इस विभाग द्वारा उचित सभानां बैक आफ इहिया, टॉकियो / भारतीय द्वतीयां, जापान से सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएंगी।

3. निदेशक ऋण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि टेक्स बसी रहूँ। विनियोग, ४-१ टॉकियो-1, कोये, चियोहा-कू, टॉकियो-100 जापान।

4. भारतीय द्वतीयां, टॉकियो।

5. अबर सचिव, जापान अनुभाग विवर मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबंध-३

(भी० ई० सी० एक० एम० सी० १ प्रश्न)

अपरिवर्तनीय साक्ष-पत्र

(माम के लिए मामू)

सेवा में,

विनांक

(सभरक का नाम भीर पता)

यह साक्षपत्र (अहो) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण कागार से ————— के दिनांक ————— के प्रत्युत्तर में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम मूलिम करते हैं कि हमारे नाम में निम्नलिखे के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए वहाँ रही हुए द्वारा उपलब्ध रहते थे; उनमें के लिए हमने अपरिवर्तनीय साक्षपत्र से ————— प्रोत्तर दिया है औ ये ये ये (— ये ये) कह सकते हैं, की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है:—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक दीक्षण

कलीभ प्रान बोडू समुद्री पोन लक्षण विल जिसमें दिए गए प्रावेशों का पूरा सेट हो। बैक पृष्ठीकृत एवं चिह्नित 'फेट' पर 'नोटिकाइड',

अस्य दस्तावेज जिसमें ————— से ————— तक लक्षण का लक्ष्यापन दिया गया हो (सविदा सं— — — — —) (यदि कोई हो) के संशर्म में मंजिल विवरण आर्थिक पोनलक्षण स्वीकृत है। वाह्यान्तरण ————— स्वीकृत है।

पोनलक्षण विल जो ————— से बाव को निधि का नहीं होना चाहिए। प्रावेशितों को ड्रॉपट ————— 19 — — — — — तक आवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस कोडिट के प्रत्युत्तर सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। 'अपरिवर्तनीय साक्षपत्र मे 19 — — — — — दिनांक ————— के प्रत्युत्तर निम्नलिखा गया भीर प्रायत्त सदाचं मे० (भैक्यां) यदि कोई हो, यह कोडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।'

हम एतद्वारा बतन देते हैं कि इस कोडिट के प्रत्युत्तर भीर इसकी शर्तों का अनुपायन करके निकलदाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर भीर प्रावेशितों का दस्तावेज का सूचितीय पर विविध स्वाक्षर किए जाएंगे।

जब यह क्रम अन्यथा रूप से विवार पूर्वक न बताया जाए कि कोडिट "युनिकार्म" कास्टम एड्रेसिंग फार इन्सेट्स कॉडिट्स (1974 रिवीजन) इटरेशनल बैम्बर आफ कामर्स, प्रिन्टिंग्स मे० 290 के अंद्रेन हैं।

सौदा करने वाले बैक के लिए विशेष अनुदेश

उपर्युक्त ऋण कागार के प्रत्युत्तर भारी कि गए बतन पत्र की अपर्याप्तियों के अनुमान विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिरूपि प्राप्त करने के बाव इस बतन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैक द्वारा भारी कि गए अंद्रेशों के अनुमान हुए ही की धनराशि का लोटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैक को यह बताने हुए हमें ड्राफ्ट और दस्तावेजों का एक पूरी सेट और इसके साथ एक प्रवाण पत्र अंद्रेश भेजन चाहिए कि शेष दस्तावेज मीठे ही हवाई डाक द्वारा।

3. कोडिट के प्रत्युत्तर सभी बैक के चर्च अपालकों/सभरकों के लिए के लिए है।

भवर्द्धय

(— — — — —)

बाणिर्जितक बैक

द्वारा — — — —

प्राविहन दस्तावेज

भुगतान शर्तः:

यह भुगतान हमारी साक्षपत्र से — — — — का अभिन्न रूप है।

1. प्रारम्भिक सुधारन

धनराशि ————— ये न, जो कि कुल सविदा मूल्य का ————— प्रतिशत है।

प्रतिविनाश दस्तावेज़

प्रस्तुत करने की अनिम निधि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि ————— ये न

जो कि कुल सविदा मूल्य का ————— प्रतिशत है।

प्रविहन दस्तावेज़

प्रस्तुत करने की अनिम निधि

3. पोनलक्षण दस्तावेजों के महे भुगतान

धनराशि ————— ये न

सविदा की कुल मूल्य का ————— प्रतिशत।

टिप्पणी—पोनलक्षण दस्तावेजों के महे पूरी भुगतान के सामने मे इस भलम दस्तावेज की अवधारणा नहीं है।

अनुबंध-६

प्रपत्र भी० ई० सी० एक० एम० सी० ०२

अपरिवर्तनीय साक्षपत्र

(सेवाओं के लिए मामू)

सेवा में,

विनांक

यह साक्ष पत्र (अहो) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण कागार से —————

विनांक ————— के अनुसार में जारी किया गया है।

(सभरक का नाम न पता)

श्रिय महाराज,

इस प्रापको सुचित करते हैं कि हमारे नाम में नियालने के लिए पूर्ण और मत्य के लिए लालकारी ड्राफ्ट एट माइट डारा उत्तरव्य रकम या रकमों के लिए प्रापके नाम में हमें अधिकारीय नामांक सं

कोत दिया है जो येर—

(येर—पहले) की कुछ धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संसाधन भूगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा सं० १८८८ और परियोजना) और संवित वस्तावेजों को लक्षी करता है। सोशा तद करने के लिए ड्राफ्ट संसाधन वस्तावेज से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी ड्राफ्ट और वस्तावेज "अपर्याप्तीय साल पत्र सं० १८८८ के अन्तर्गत जून लिए गए हैं" से अधिक होने चाहिए।

यह कोहिट हस्तानरजीय नहीं है।

इस एतद् डारा बचन देते हैं कि इस कोहिट के अन्तर्गत इसकी जाती रकम अनुसार करके अनुए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और मार्गिकी को वस्तावेजों की सुपुर्णी पर विधिवत् स्थीकार किए जाएं।

यह तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बनाया जाए यह कोहिट "प्रूफिकार्ड कस्टम एंड प्रैसिट्स फार डाक्यूमेंटरी कोहिट्स (1974 रिलीजन) उत्तरव्यक्तम रूपरक्षण आफ कामस" बोरर सं० २९०" के प्रवीन है।

सोशा करने वाले लिंक को विशेष अनुदेश:—

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (जहाँ और इसके मानोनीत प्राप्तिकारी, डारा जारी किए गए निष्पादन के भूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस कोहिट के अन्तर्गत भूगतान इसमें संलग्न शीट में नियांरित भूगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारंभिक भूगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बड़ाए नामांकों विवरण का प्राप्तिकर्ता है।

2. ऊपर उल्लिखित ज्ञान समझौते के अधीन जारी किए गए वस्तावेज के उपर्युक्तों के अनुसार विवेशी प्राप्तिक सहयोग निषिं से इपने भूगतानों के लिए प्रमिलुनि प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि को मानोनीत करने वाले लिंक डारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का बचन देते हैं।

3. ऊपर्युक्त पत्र 1 में यथा उल्लिखित वस्तावेज की एक प्रति और २ सं० १८८८ की प्रति के द्वारा बाल ही देते जाएंगे।

4. इस साल के अन्तर्गत वेक के सभी वर्ष भायालकों/संभरको के लिंक के लिए ।

वस्तवीय
(वाणिजिक वेक)

डारा
(प्राप्तिकर्ता अनुदान)

भूगतान अनुसूची

यह भूगतान अनुसूची ड्राफ्ट सालपत्र सं० १८८८ का एक अधिक अग्र है।

- प्रारंभिक भूगतान धनराशि येर
कुछ संविदा भूल का प्रतिशत है
अपेक्षित वस्तावेज, लालकारी विवरण
प्रस्तुत करने की अपेक्षा निषि।

२. भूगतान वृद्धि

नपूर्ण योग की धनराशि येर
कुछ संविदा भूल का प्रतिशत
नियम प्रकार से भूगतान किया जाना है

वेय धनराशि]

वर्तित भूगतान विधि

येर येर

पहली जिस्त येर
द्वितीय जिस्त येर

प्रयोक्षित वस्तावेज (जहाँ अधिकार उपके मानोनीत प्राप्तिकारी) डारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक
संदर्भ सं०

मेशा में,

(संभरका का नाम और पता)

संदर्भ नाम करार सं० के प्रत्यक्षता
परियोजना से संबंधित के नाम में
येर के लिए डारा जारी किए गए साल पत्र की सं०
दिनांक ।

मैं प्रधोहन्मालरी प्रतिनिधि (जहाँ) एन्ड्राया
प्रोर के वीच संविदा मं०
दिनांक में निहित भूगतान की जाती के प्राप्ति समुद्र पार
प्राप्तिक स्थायता निषि द्वारा
की धनराशि (..... येर के लिए) प्राप्त करने
के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हू।

(.....)

(जहाँ)

डारा.....

(प्राप्तिकर्ता अनुदान)

विशेष अनुदेश:—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में वर्णिया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 45—ITC (PN) 82

New Delhi, the 18th September, 1982

SUB : Licensing conditions for import of goods and services under OECF loan agreement No. ID-P. 18 of Yen 1.8 billion (Bombay sub-urban Railways Modernisation Project).

File No. IPC/23 (33) 82.—The terms & conditions governing the issuance of import licence in respect of goods & services under OECF loan Agreement No. I.D.-P.18

of Yen 1.8 Billion for the implementation of the Bombay Suburban Railways Modernisation Project, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller Imports & Exports

**APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE NO. 45-ITC (PN) 82,
dated, the 18th September, 1982**

**LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF IMPORTS OF
GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT OF
YEN 1.8 BILLION FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE BOMBAY SUBURBAN RAILWAYS MODERNI-
ZATION PROJECT EXTENDED BY THE OVERSEAS ECO-
NOMIC CO-OPERATION FUND (OECF) OF JAPAN**

Section I—General conditions

I. (i) The Yen Credit of 1.8 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Bombay Suburban Railways Modernization Project is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I. (ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/OG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed 2,000 million (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 18". first and second suffix licence code will be "SJC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to the Indian Railways, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I. (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of the Indian Railways on CIF basis.

I. (iv) Depending on the convenience of the Indian Railways more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed 2,000 million (CIF) as specified at (i) above.

I. (v) The extension of the validity of the import licence, may on application by the Indian Railways, be granted upto 31-12-86. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I. (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I. (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I. (viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas Supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licencse on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on

Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I. (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I. (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

"..... Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-86.

**Section II—Special points to be kept in view while negotia-
ting a supply contract.**

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude India Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :—

- Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

- Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- Where the number of qualified suppliers is limited.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it appropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

- (i) Formal Selective International Tendering.
- (ii) Informal International Competitive Procurement.
- (iii) Direct Purchases from a single supplier.

The Indian Railways shall submit to the Fund (OECF) immediately after conclusion of the Loan Agreement for its review copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings, reports of the analysis of bids, proposal for awards, and all other documents relevant to the bidding. These documents may be forwarded to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, in duplicate, for onward submission to the OECF.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.18 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier.

The Suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or Juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract.

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (Name of Company) has been incorporated and registered in _____ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries "

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent

(30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae :

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 14th May, 1982 concerning the Yen Credit No. ID-P.18 (Project Aid) for Bombay Suburban Railways Modernization Project and will be subjected to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P.18 dated 14th May, 1982 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.
- (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vi).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply of contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo, informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the imported after each shipment giving the necessary details, and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF.

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both Indian Railways and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P.18 (Project Aid) for Bombay Suburban Railways Modernization Project.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, Indian Railways and the CAA & A will be informed of the same. Whereafter the Indian Railways should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA & A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building,

Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA & A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas supplier concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA & A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA & A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the Letter of Credit will be either to the account of overseas suppliers or the importer. B.O.I., Tokyo, will therefore, recover all these charges from the suppliers' Bank or the importer, charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers/importer.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I., Tokyo will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M/O Finance) on 25th March, 1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the Indian Railways vide Section VI (iv) infra.

Section VI—Responsibility for rupee deposit.

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974.

The importer will take delivery of the imported goods only after producing the original shipping documents obtained from the Banker after depositing the rupee equivalent of the foreign currency payment made to the supplier. Permission of the Controller of Aid Accounts and Audit, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi should be obtained for any departure from this procedure. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in public Notices No 102-ITC (PN)/74 dated 3rd August 1974 and No 8-ITC (PN)/76 dated 17th January, 1976 or as may be notified by Government from

time to time through Public Notices of the CCI & E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc abroad—Purchase under credits/Loan Agreements" Loans from the Government of Japan—1.8 Billion Yen Credit No. ID-P. 18 for Bombay Suburban Railways Modernization Project. The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974, will however, not be applicable as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68 dated 30th August, 1968, No. 233-ITC (PN)/68 dated 24th October, 1968, No. 132-ITC (PN)/71 dated 5th October, 1971 No. 74-ITC (PN)/74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC (PN)/76 dated 12th October, 1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN)/71 dated 5th October, 1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA & A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA & A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo to B.O.I., Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA & A will be issuing suitable advices.

Section VIII—Miscellaneous provisions.

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence.

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII(iii) Disputes.

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure—III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII(iv) Future Instructions.

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P. 18 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII(v) Breach or violation.

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures.

Annexure—I List of eligible source countries.

Annexure—II Broad Guidelines for Procurement.

Annexure—III Request for issue of Letter of Authority.

Annexure—IV Form of Letter of Authority.

Annexure—V Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola
Botswana
Burundi
Cameroun
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of
Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger

Portuguese Guinea

Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and Dep (2)
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terra, Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Island Inaccessible, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Guracao, Saba, Fustic, St. Martin (Southern part).

America, North & Central

West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman

VI. ASIA, South
 Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 India
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka

VII. ASIA, Far East
 Brunei
 Hong Kong
 Khmer Republic
 Korea, Republic of Laos
 Macao
 Malaysia
 Philippines
 Singapore
 Thailand
 Thailand
 Timor
 Viet-Nam, Rep. of
 Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA
 Cook Islands
 Fiji
 Gilbert & Ellice Is.
 French Polynesia (5)
 Nauru
 New Caledonia
 New Hebrides (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (US) (6)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

IX. Europe
 Cyprus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

- (1) Main islands : Atigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands; Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshal Islands and Marine Islands (except Guam).

(a2) Member of Association Countries of OPEC :

Algeria
 Bolivia
 Libyan Arab Republic
 Gabon
 Nigeria
 Ecuador
 Venezuela
 Iran
 Iraq
 Kuwait
 Qatar
 Saudi Arabia
 Abu Dhabi
 Indonesia

Main guidelines for procurement of goods and services under the Project Loans as formulated by OECF :

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India

II. Bidding Documents and Contracts

II-1. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3 Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible Suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions :

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses.—Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labours and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance.—The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order of confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract :

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as _____ per cent (%) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country), and _____ per cent (_____) of the directors are nationals, _____ (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)".

IV-1. Standards.—If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications, should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names.—Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money.—Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V Liquidated Damage.—Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure.—The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes.—Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which

have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation.—Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing

IX. Bid Opening Evaluation and Award of Contract :

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids.—The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures.—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alteration of Bids.—No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be Confidential.—Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids.—Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders.—In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids.—Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower, if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless, there should be a change in the value of currencies before the award is made.

In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids.—Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract.—The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

Request for Issue of the Letter of Authority

No.

DATE :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O. Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub.—Import of from Japan under the
Yen Credit No. ID-P. 18 (Project Aid) for 1979-80.

Sir,

In connection with the import of from under the above mentioned Yen Credit No. ID-P. 18 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the(name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in yen).
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the Overseas Supplier;
- (l) Nationality.

- (ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.
- (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier.
- (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (1) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (including No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank of India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE-IV

(Letter of Authority Form)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Yen Credit (Project Aid).—Loan Agreement No. ID-P. 18-Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen _____ favouring M/s. _____ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto _____.

Yours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____.

2. Importers' Banker _____. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968, 233-ITC(PN)/68 dated 24th October, 1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12th October, 1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances-843-Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan 1.8 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 18 for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The Banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Otemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE-V

Form OECF-LCI

Irrevocable Letter of Credit (Applicable for goods)

To
(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____, dated _____, between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of _____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y _____ (Say yen) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in
Full set of clear on board ocean bills of lading
made out to order and blank endorsed and marked
"Freight"

and "Notify" Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. _____ (if any) from _____ to _____ Partial shipments are _____ permitted. Transhipment is _____ permitted.

Bills of lading must be dated not later than _____. Draft must be presented for negotiation not later than _____. All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under _____ irrevocable credit No. _____ dated and Import Reference No(s) _____ (if any)." This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :—

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.
2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to _____.
3. All banking charges under this credit are for the account of the imports/supplies.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By :

(Authorised Signature—)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount : Y _____ being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : _____ being _____ % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : _____ being _____ % of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE-VI

Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

To _____

(Name and address of the Supplier)

Date :

This Letter of Credit has been issued pursuant to _____
Loan Agreement No. _____
dated.....
between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION ON FUND

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of _____ (Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. _____ with regard to _____ Project). Drafts must be presented for negotiation not later than _____

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____ dated".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

- After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the imports/supplies.

Yours Faithfully,

(a commercial bank)

By :

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.

I. Initial Payment

Amount : Y being % of the total contract price

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Agreement amount: Y being % of the total contract price to be paid as follows :

Amount due _____ Latest presentation date _____

Ist Instalment : _____

2nd Instalment : _____

Required document: a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date:
Ref. No.

To _____

(Name and address of the Supplier)

Re: Letter of Credit No., dated _____
issued by _____ in favour of _____
for Y concerning Project
under Loan Agreement No.

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle to receive the sum of Y (Yen) on from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No., dated between and _____

(Borrower)

By:

(Authorised Signature)

Special Instructions:

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

